Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

कोरोना संकट और हमारा दायित्व

रेशमा त्रिपाठी
शोधार्थी पीएचडी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।

Article Info
Volume 4 Issue 3
Page Number : 62-68

Publication Issue :
May-June-2021

Article History
Accepted : 20 June 2021
Published : 30 June 2021

सारांश– कोरोना संकट के समय अपने मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोगों की सहायता करें, पर ज़रूरी नहीं है कि वह सहायता आर्थिक ही हो। मनुष्य की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं यदि हम किसी को कुछ दिन छत दे सकते हैं, कुछ दिन रोटी दे सकते है और कुछ कपड़े अपने हिस्से का उसे दे सकते हैं तो वह भी हमारी मदद ही होगी, साथ ही सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना भी समूचे भारत में शान्ति सौहार्द, एकता और अखण्डता बनाये रखना भी देशहित में सहायक होगा। अब हमें, और आपको यह तक करना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती हैं हमारा जनजीवन पहले जैसा सामान्य नहीं हो जाता हैं तब तक हमें अपने दायित्वों का निर्वाहन भलीं–भांति करना चाहिये। जिससे इस संकट की स्थिति में देश, आप और हम बाहर आ सकें।

मुख्य शब्द– कोरोना, संकट, समाज, आर्थिक, मनुष्य, मानसिक, वैक्सीन,देशहित, पालन।

कोरोना संकट का आम आदमी के जीवन में शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जिस पर प्रभाव न पड़ा हो। विश्व स्तर पर भी यह संकट एक महामारी के रूप में बनकर उभरा। पिछले 6 महीनों से कोरोनावायरस से बचाव के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी हैं रोजमर्रा की दौड़ती, भागती जिंदगी के बीच अचानक ब्रेक लगने से मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक संकट पर गहरा असर पड़ा हैं इंडियन सैंकेट्रिक सोसाइटी के एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना काल के दौरान मानसिक रोगियों में इजाफा 15 से 20 प्रतिशत तक हुआ हैं। इसका मुख्य कारण तीन बातों पर केंद्रित हैं–

1. कोरानावायरस से संक्रमित होने का डर।
2. नौकरी और रोजगार को लेकर अनिश्चितता।
3. लॉकडाउन के कारण अकेलापन।

गौरतलब हैं कि सरकारी नौकरी और रोजगार की समस्या निम्नवर्ग से लेकर मध्यवर्ग तक अधिक प्रभावी होंगी। जिसमें कोरोना संकट के समय 2.1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। जिसमें पिछले 6 वर्षों के दौरान 25 से 64 की उम्र के लोग शामिल हैं। जिनकी वर्तमान संख्या लगभग 47 मिलियन है जिसमें 3.5 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की जरूरत हैं जिसमें श्रम शक्ति की भागीदारी के अनुसार 30 लाख युवकों को रोजगार देने की जरूरत हैं प्रतिमाह लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत की श्रम शक्ति भागेदारी 40 फीसदी ही हैं जबकि विकसित देशों में 60 फीसदी हैं इस बात पर भी सरकार

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हैं क्योंकि चीन जनसंख्या की दृष्टि में भारत से आगे होते हुए भी रोजगार के मामले में अधिक जागरूक हैं। अतः सरकार को सार्वजनिक नौकरियों को खत्म करने के बजाय उसमें इजाफें करने की जरूरत हैं। स्टैण्ड–अप, स्टार्ट अप इंडिया और मुद्रा योजनाओं पर अमल कर उद्यमियता की भावना को जगाने का प्रयास करना चाहिये। क्योंकि देश में बेरोजगारी दर पिछले तीन सालों में 4 फीसदी से ऊपर है जिसे सरकार जनसंख्या बोझ समझकर नजर अंदाज करती हैं बजाय उसमें संशोधन करने के। देश में वर्तमान समय में 83 मिलियन नौकरियों की जरूरत हैं। जिसमें रेलवे का निजीकरण भी चिंता का विषय है, साथ में मनरेगा में भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत हैं। हालांकि कोरोना संकट के समय इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी हैं साथ ही यह तय कर पाना मुश्किल कि आगे की राह किस प्रकार विकसित होगी क्योंकि मानसिक द्वंद्व से लेकर आत्महत्या, चोरी, लूटपाट, भिक्षावृत्ति इत्यादि में इजाफा होना तय हैं। वहीं महिलाओं/बालिकाओं के संदर्भ में घरेलू हिंसा यौन शोषण में वृद्धि देखने को मिली हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग अनुसार– लॉकडाउन के दूसरे चरण तक करीब 92000 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। वही रेप के मामलों में 7 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। एन.सी.आर.बी. ने 2019 के आंकड़े जारी किये जिसमें पिछले साल हर दिन दुष्कर्म के 87 मामले दर्ज हुये हैं। इस तरह साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 मामले दर्ज किये गये जो कि 2018 की तुलना में 7 प्रतिशत से अधिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ 3,78,236 आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे। रिश्तेदारों से क्रूरता के मामले 30.9 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत अपहरण के मामले सामने आये हैं। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो एक अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन की मार देशभर में करीब 78 प्रतिशत से ज्यादा लोगों पर पड़ी है यह सर्वेक्षण 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 169 जिलों में किया गया है यदि आर्थिक आधार पर वर्ग भिन्नता पर प्रकाश डालें तो गरीब वर्ग 82 प्रतिशत, समग्र 70 प्रतिशत और कुल लगभग 78 प्रतिशत लोगों पर कोरोना का असर देखने में आया हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर कृषि मांस, मत्स्य उत्पादन, रेलवे, फिल्म उद्योग पूरी तरह से ठप होने के कारण जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जीएसटी संग्रह पर अभी भ्रामक स्थित हैं क्योंकि रेस्तरां, विमानन् उद्योग, रेलवे जैसे सेवा क्षेत्र महज 30/40 फीसदी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि कोरोना संक्रमण काल से पहले हर दिन 14,000 पैसेंजर ट्रेन चलायी जाती थी लेकिन आज सिर्फ 400/500 ट्रेनें की चल रही हैं। इसी तरह हवाई सेवाएं भी पूर्व की तुलना में 30/40 फीसदी यात्री यात्रा कर रहे हैं। मेट्रो का भी यही हाल है। इस तरह कुल संग्रह में 71.75 फीसदी पिछले साल की तुलना में कमी आई हैं। मई 2020 से सुधार क्रम शुरू तो हुआ परन्तु जुलाई में फिर हमें निराश होना पड़ा। जून में जहां 9.03 फीसदी की गिरावट हुई थी वहीं जुलाई में 14.36 फीसदी गिर गई। जीडीपी मतलब सुधार के बजाय बिगाड़ के संकेत दिखने लगे। अब सितम्बर में 3.88 फीसदी की बढत दिखाई जा रही हैं, उससे यकीनन अर्थव्यवस्था के तमाम अंगों पर बेहतर प्रदर्शन होगा। जीएसटी संग्रह 10.4 की बढ़त मायने रखती हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही घट रहा हो लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चों से सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा हैं। यह रिसर्च साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ हैं जिसमें शोधकर्ताओं का कहना कि विकसित देशों की तुलना में भारत में 40 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु वर्ग में कोरोना के अधिक मामले सामने आयें हैं। यह भी पता चला कि 70 फीसदी से ज्यादा मरीजों ने अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को संक्रमित नहीं किया। सिर्फ आठ फीसदी संक्रमितों से 60 प्रतिशत नए लोगों तक संक्रमण फैला। कोरोना से मरने वालों की संख्या में तीन तरह के लोग शामिल हैं। पहला, 63 प्रतिशत मृतक ऐसे लोग पहले से किसी एक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त थे। दूसरा, 36 प्रतिशत लोगों को पहले से दो या

दो से अधिक बीमारियों से ग्रसित थे। तीसरा, 45 प्रतिशत लोग जो मधुमेह से पीड़ित थे। ऐसे लोग कोरोना वायरस की सपेट में आने से मरने वालों की संख्या में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिमाह कोरोना से मरने वाले मरीजों में इजाफा हो रहा हैं। मई में मरने वालों की संख्या 4267 थी, जून में 11988 जुलाई में 19122 अगस्त में 28859 और वहीं सितम्बर में 33255 मामले दर्ज हैं। वहीं गौरतलब हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश हैं जिस पर सरकार का ध्यान केंद्रित मंत्री गंगवार जी ने कहा है कि देश का कृषि बजट 1.34 लाख करोड़ रुपये हुआ। उनका मानना हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2014 मे पदभार संभालने के बाद गांवों, किसानों, गरीबों और कृषि की निरंतर प्रगति हुई हैं। उन्होंने कहा वर्ष 2009/2010 में कृषि मंत्रालय का बजट सिर्फ 12,000 करोड़ रुपये था, जिसे 11 गुना बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया हैं। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये राष्ट्रपति ने तीनों श्रम कानूनों पर अपनी सहमति भी दे दी हैं। गौरतलब हैं कि सरकार के कानून कागजों पर और बजट कुछ समझदार किसानों तक ही पहुंच पाते हैं। धरातल पर नून रोटी की खातिर दिन रात मेहनत, गालियां और चमचों की खातिरदारी में किसान अपने ही घर में न जाने कितनी रातें भूखे सो जाते हैं और अगली दफा, अगली सरकार, अगला बजट पारित हो जाता हैं फिर ऐसी क्या वजह हैं कि वहीं किसान और अधिक गरीब, कर्जदार हो जाता हैं। यकीनन कोई तो राजनीति होगी या सरकार किसानों का निजीकरण चाहती हैं विचार करना चाहिए। क्योंकि किसान से खरीदकर किसान को ही कम दाम में सरकारी कोटे द्वारा राशन कार्ड से राशन देना वाकई कई प्रश्न खड़े करता हैं वहीं गौरतलब हैं कि कोरोना संकट का असर।

बाल मजदूर और पिछड़ी जातियों पर अधिक प्रभावी रूप में देखने को मिलेंगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट की मानें तो विश्व में 117 देशों की सूची में भारत 102वें पायदान पर हैं भुखमरी के क्षेत्र में लिहाजा भारत की स्थिति चिंताजनक हैं अन्य देशों की तुलना में क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 66वीं, बांग्लादेश 94वें स्थान पर अपना अधिकार बनाने में कामयाब रहा यही मानना कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेस्ट हंगर हिल्फ की ग्लोबल हंगर इंडेक्स और यूनिसेफ का भी मानना हैं और यदि हम कोरोना काल पर नजर डालें तो हाल ही में आयी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आई रिपोर्ट की मानें तो – 'covid 19 and child labour a time of crisis a time of act' नामक रिपोर्ट में मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण बाल श्रम में वृद्धि की संभावना जताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह महामारी आर्थिक संकट लेकर आएगी जिसमें लाखों बच्चों के धकेले जाने का खतरा बना हुआ हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील और मैक्सिकों जैसे देशों की चर्चा की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वर्ष 2000 में करीब 24.6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे जो 2017 में घट कर 15.2 करोड़ रह गये थे। इनमें से 7.3 करोड़ बच्चे उन कामों को कर रहे थे जो कि बेहद खतरनाक माना जाता हैं।

यदि अधिकतम आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया में अफ्रीका में सर्वाधिक बाल मजदूर पाये जाते हैं करीब 7.21 करोड़ बच्चे वहीं अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में 1.07, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 55 लाख, अरब देशों में 75 लाख बाल बच्चें बाल मजदूरी कर रहे हैं। कुल मजदूरों में करीब 48 फीसदी बच्चें 8 से 11 वर्ष के जबकि वहीं 28 फीसदी 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। यदि भारत की बात करें तो बाल मजदूरी के मामले 2011 की जन गणना के मुताबिक 10.1 मिलियन बच्चें बाल मजदूरी कर रहे थें जिसने 5.6 मिलियन लड़के जबकि 4.5 मिलियन लड़कियां काम कर रही थी। स्पष्ट हैं कि बाल मजदूरी का अनुपात

कृषि क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप में सक्रिय हैं। हालांकि भारत से लेकर विश्व स्तर तक पिछले कुछ दशकों से बाल मजदूरी में गिरावट लगातार देखने को मिल रहा हैं जिसमें भारत सरकार समय–समय पर बाल मजदूरी पर प्रतिबन्ध लगाने से लेकर विभिन्न सेवाओं के साथ कानून का पालन करने पर बल देने, लोगों को जागरुक करने का समग्र प्रयास कर रही हैं किन्तु बाल मजदूरी जड़ता में इस तरह विद्यमान हैं कि इसका अनुपात कोरोना काल में बढ़ कर देखने को मिल सकती हैं लिहाजा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 20 वर्षों से जो गिरावट देखने को मिली हैं वह इस संकट के दौर में पुनः बढ़ती हुई आगे उभर कर आएगी जिसका असर भी लम्बे समय तक देखने को मिल सकता हैं। बाल मजदूरी का जन्म यदि गरीबी के कारण होता हैं तो उसका दूसरा पहलू यह भी हैं कि बाल मजदूरी के कारण गरीबी जन्म लेती हैं। यह समझना आवश्यक हैं कि कल कारखानों में काम करने वाले बच्चें सस्ते दामों पर अधिक काम, अधिक समय तक करते हैं जिसके कारण वयस्कों को रोजगार मिलने में बाधा उत्पन्न होती हैं। वहीं दूसरी ओर गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का जनसंख्या की दृष्टि में कम होना, योग्य एवम् कुशल उपभोगकर्ता का आभाव होना हैं।

एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल मजदूर औसतन 12 घंटे काम करते हैं ऐसे में सस्ता मजदूर मिल जाने पर वयस्कों को रोजगार कैसे मिल सकेगा लिहाजा गरीबी के कारण भुखमरी बढ़ती हैं और तब फिर जन्म ले लेता है बाल मजदूर इसका एक कारण यह भी है कि औद्योगिक क्षेत्र में संलिप्त होने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पढाई बीच में छोडने का कारण भी प्रत्यक्ष रूप में गरीबी ही हैं और यदि हम उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों की साक्षरता दर का अनुमान देखें तो साफ पता चलता हैं कि वह संख्या के अनुपात के अनुसार कितने निचले पायदान पर खड़ा हैं। अक्सर देखने को मिलता हैं कि बाल मजदूरों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता हैं परिणाम स्वरूप असमय मृत्यु, विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं साथ ही दुर्व्यवहार, असुरक्षित प्रवासन, यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद – फरोख्त, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का करोबार, बाल अपराध जैसी बड़ी समस्या देश के समक्ष आती हैं जो कि बेहद संवेदनशील और प्रासंगिक विषय हैं जिस पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हैं। वहीं यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो कोरोना संकट के समय सर्वाधिक अनुकूल वातावरण रहा जिसमें नदियों के स्वच्छ होने से लेकर वायु प्रदूषण तक अधिक प्रभावी रूप में देखने को मिला जो ही बेहद खास रहा। क्योंकि पर्यावरण का जितना प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता हैं उतना ही पशु, पक्षियों, जंगली जानवरों पर भी देखने को मिलता हैं। अपितु देखने में आया हैं कि बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, हो गई हैं उन्हीं में से एक भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ भी मानो इसकी चपेट में आने लगा हैं क्योंकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 71 बाघों की मौत सितम्बर माह 2020 में हो गई। यदि पिछले तीन सालों पर नजर डालें तो कुल 384 बाघों की मौत हो गई जोकि चिन्ता का विषय हैं। सरकार का ध्यान इस विषय पर भी खींचने की आवश्यकता हैं। गौरतलब हैं कि कोरोना को लेकर दुनियाभर में चीन के प्रति विरोधी भावना जिस तरह से कारोबार पर असर डाला हैं उसमें भारत भी पीछे नहीं हैं। पहली बार चीन के मुरीद ग्राहकों और देशों ने भारतीय निर्याताकों से सम्पर्क साधा हैं। जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, कालीन, सैंडलरी, मीट, डेयरी, रसायन सहित एक दर्जन उद्योगों को मिल रहा हैं यही वजह हैं कि कोरोनाकाल में पहली बार निर्यात पांच फीसदी बढ गया। कोरोना से बचाव के लिये मास्क सबसे पहले चीन ने पूरी दुनिया में उतारे। एन–95 मास्क के लिये मारामारी मच गई। लेकिन भारत ने महज पांच

माह में मास्क में न केवल आत्मनिर्भरता हासिल किया बल्कि 22 देशों से चीन का बाजार छीन लिया। अब भारत से दुनिया में मास्क निर्यात हो रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के सलाहकार वाई एस गर्ग के अनुसार दो माह में नये बाजार के तौर पर बांग्लादेश, अफ्रीकी देश, जर्मनी, जापान और अमेरिका के नये ग्राहकों को माल निर्यात किया गया हैं। पिछली बार मासिक निर्यात में 5.27 फीसदी की वृद्धि हुई हैं। इनमें जिन शहरों ने अहम भूमिका निभाई वह हैं– अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, मेरठ, कानपुर आदि ने। इस पर केदारनाथ सिंह जी की एक कविता याद आती हैं कि–

'चट्टानों को तोड़ो
वह सुन्दर हो जायेगी
उसे तोड़ो
वह और, और सुन्दर होती जायेगी
अगर कन्धे दुःख रहे हो
कोई बात नहीं
यकीन करो उन कन्धों पर
कंधों के दुखने पर यकीन करों
यकीन करों
और खोज लाओ
कोई नयी चट्टान।।'

भारत का आत्मनिर्भर बनने का संकल्प इसी कविता के भाव में निहित हैं और स्वयं के भीतर झांकने पर निश्चित ही हमें, आपको मिल जायेगी। इतना संकट होने के बाद भी भारत ने विविधता से भरपूर होते हुए भी एकता एवं अखण्डता का परिचय दिया जिसमें गरीब, मजदूर, असहाय जन्य लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिये सड़कों पर पैदल चलने से लेकर भूख से तड़प कर मर जाने तक का सफर तय किया। जिसमें परिवारजन का विक्षोह, अन्तिम दर्शन न कर पाना, बच्चे को बिलखता छोड़, भूख की तड़पन से लिप्त होने के बाद भी जिस तरह शांति का परिचय दिया यकीनन सभी जन सम्मान और आदर के हकदार हैं। इस संकट की घड़ी में जिस तरह देश में शांति, सौहार्द कायम रहा। इससे स्पष्ट हैं कि भारत पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि पड़ोसी देशों पर प्रभाव दिखाई देता नजर आ रहा हैं। दिसम्बर के अंत तक पाकिस्तान गेहूं के बड़े संकट का सामना कर सकता हैं। यह रिपोर्ट नेशनल असेंबली स्टैण्डिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने दी हैं जिसके अनुसार संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 15 लाख टन गेहूं खरीदना चाहती हैं ताकि आपूर्ति के अन्तर को खत्म किया जा सकें। इसी तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाये जा रहें हैं। विशेषज्ञों का मानना हैं कि अमेरिका कम्पनियों के नतीजे बाजार को प्रभावित करेंगे।

यदि सामाजिक संदर्भ में बात करें तो अपवाद छोड़कर सभी धर्म संप्रदाय एवं समुदाय के लोगों ने कोरोना संकट के समय सामाजिक, पारिवारिक, पारंपरिक, तीज–त्यौहार, ईद, रमजान, होली संभावना हैं आगामी पर्व दीपावली–आमावस्या आयोजन में सजगता, सतर्कता एवं डब्लूएचओ के बताये नियमों और सरकारी आदेशों का पालन करते हुए कोरोनावायरस से बचाव करते हुये अपने–अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे जैसा कि अभी तक करते आये हैं। भारत देश की वर्तमान स्थिति आजादी के बाद की आर्थिक स्थिति के बराबर पर लगभग

पहुंच गई हैं फिर भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी गहरी पैठ हासिल की, जो कि देश के लिये गौरव का विषय हैं। जब समूचा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा हैं तब भारत की संस्कृति, परम्परा, योग–ध्यान, खान–पान, औषधि के रूप में काम आया फिर वह सात्विक आहार हो, ध्यान हो, नमस्ते मिलाप हो या समानान्तर शारीरिक दूरी हो सभी ने अपनी ओर ध्यान आकार्षित किया साथ ही समय रहते देश भर में लॉकडाउन घोषित करना भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सराहनीय कदम रहा। वहीं गौरतलब हैं कि कोरोना संकट में परिवार का ध्यान रखें, डब्लूएचओ के दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार रोजमर्रा की जिंदगी में अनुकरण करें, जिसमें भारतीय संस्कृति को अपनाने से लेकर मुंह पर मास्क लगाना, सात्विक भोजन करना स्वच्छता का पालन करना समानांतर दूरी बनाए रखना, योग, ध्यान, प्राणायम पर बल देना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनाना इत्यादि बातों पर विशेष अमल करना चाहिये। रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है इसमें से एक तिहाई बहुमत से मजदूर हैं जिनकी सहायता नगद भुगतान में बढ़ोत्तरी करके, मनरेगा श्रमिकों को नगद देकर, बाद के लिये काम की गारंटी देकर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग सहायता राशि द्वारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, कोटेदार, जमींदार, संगठनों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा, गरीबों, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक मजदूर वर्ग की सहायता नगद खाद्यान्न रसद आपूर्ति के साथ–साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करवाते हुये अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। यह एक सामाजिक प्रतिष्ठित आर्थिक संपन्न व्यक्ति द्वारा प्रवासी भारतीयों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये जैसे कि महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने सराहनीय कार्य किया उसी तरह समाज के हर जनपद के जैसे कि प्रयागराज में एनजीओ संगठन आई डीयू लुक स्मृति सेवा संस्थान अभिषेक वर्मा जी ने सराहनीय कार्य किया है। लखनऊ से भरोसा आरिफ जफर ने अपने साथी डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया साथ ही प्रतापगढ़ जनपद से सीसी बीपीडीयू द्वारा अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा बहुत ही सामाजिक एवं सराहनीय कार्य किये गये। इसी तरह हमारा दायित्व बनता हैं कि हम अपने से नीचे तबके के लोगों की सहायता करें यदि सरकारी विभागों की बात करें तो बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाकर, घर से काम करने, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन, वार्तालाप, कार्यक्रम एवं विभागीय कार्य संपन्न कराये जायें जोकि सरकार ने सक्रिय रूप से लागू किया, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान बच्चों की शिक्षा पर देखने को मिले मिलेगा यकीनन किन्तु डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, प्रेरणा ऐप द्वारा बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चाहिये। लेकिन यह व्यवस्था संकट काल तक ही सीमित रखा जायेगा तो ही बच्चों के लिये बेहतर होगा। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा नहीं तो इसका परिणाम साइबर क्राइम जैसे जघन्य अपराधों की ओर बढ़ावा देना होगा क्योंकि भारत को देखना हो तो गाँव से, मलिन बस्तियों से, फुटपाथों से देखो यकीनन स्वतंत्र एवं परतंत्र भारत में तुलना कर पाना मुश्किल होगा। अतः हमारा दायित्व बनता हैं कि कोरोना संकट के समय अपने मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोगों की सहायता करें, ज़रूरी नहीं है कि वह सहायता आर्थिक ही हो। मनुष्य की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं यदि हम किसी को कुछ दिन छत दे सकते हैं, कुछ दिन रोटी दे सकते है और कुछ कपड़े अपने हिस्से का उसे दे सकते हैं तो वह भी हमारी मदद ही होगी, साथ ही सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना भी समूचे भारत में शान्ति सौहार्द, एकता और अखण्डता बनाये रखना भी देशहित में सहायक होगी। अब हमें/आपको यह तक करना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती हैं हमारा जनजीवन पहले जैसा सामान्य नहीं हो जाता हैं तब तक हमें अपने दायित्वों का निर्वाहन भलीं–भांति करना चाहिये। जिससे इस संकट की स्थिति में देश, आप और हम बाहर आ सकें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करें।।

सन्दर्भ सूची–

1. द हिन्दू में प्रकाशित लेख
2. दृष्टि आडियो आर्टिकल 395
3. केदारनाथ सिंह की कविता– चट्टान को तोड़ा
4. दैनिक समाचार में प्रकाशित आंकड़े 2020–21
5. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2020
6. डब्लू० एच० ओ० द्वारा जारी कोरोना के आँकड़े 2020–21